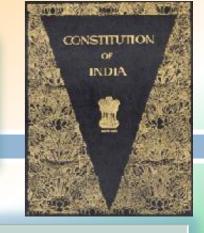


मेरे प्यारे देशवासियो आओ देश बचाएँ

आओ CAA + NPR (NRC) का बहिष्कार करें

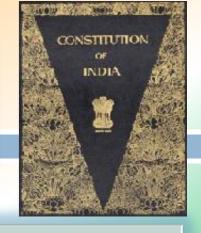
RSNS Rashtirya Samajik Nyay Sangthan





यह CAA + NPR (NRC) हमारे संविधान के खिलाफ है, क्योंकि अनुच्छेद 14, 15 के खिलाफ है, इन अनुच्छेदों के तहत धर्म-आधारित भेदभाव करना वर्जित और अस्वीकार्य है। जबकि सीएए धर्म-आधारित भेदभाव को सही ठहराता है। उदाहरण के लिए, असम में जो मुसलमान एनआरसी से बाहर हैं, उन्हें डेंटेशन भेजा जाएगा, भले ही वह पूर्व राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन साहब के घर वाले हों, दूसरी तरफ, एनआरसी से बाहर आने वाले आगर मुसलमान नहीं हैं बल्कि अन्य समुदाय के हैं तो उन के नागरिक बनने का CAA द्वार दरवाजा खुला है। और यह सिर्फ असम की बात नहीं है, बल्कि सरकार इसे पूरे देश में लागू करना चाहती है।

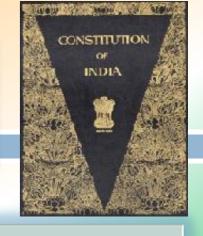




यह CAA + NPR (NRC) देश की धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, यहां राज्य में धर्म का कोई हस्तक्षेप नहीं है। १९४७ में स्वतंत्रता प्राप्त करते समय हमारे पूर्वजों ने ये तय किया था कि यह देश एक धर्मनिरपेक्ष देश होगा, सरकार और शासन का कोई धर्म नहीं होगा; और हर वयक्त को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता होगी। सीएए + एनआरसी के पीछे की सोच इस धर्मनिरपेक्ष देश को एक मनुवादी और हिंदू राष्ट्रवादी बनाने के लिए काम कर रही है, जो इस देश की धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है।

P. 02

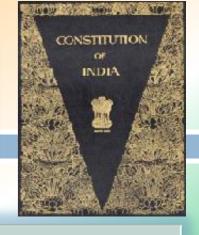




यह CAA + NPR (NRC) देश की सुरक्षा के खिलाफ है; इस देश को आंतरिक और बाहरी खतरों का सामना होगा, हमारा प्यारा देश जिन दुश्मन देशों की नजरों में खटकता है, वो अपने एजेंटों को भेजकर या उन तीन देशों से कुछ लोगों को खरीदकर भारत की सुरक्छा को नुक्सान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। जहां तक आंतरिक जोखिम का संबंध है, इन तीन देशों में से कसी देश से उत्पीड़ित हो कर आने वाला शरणार्थी यदि दस्तावेजी तौर पर खुद को इन तीन देशों में से एक का नागरिक साबित नहीं कर सका, और नागरिकता प्रापत नहीं कर सका तो वह इस देश के लिए खतरा हो सकता है। हम इस देश में हमेशा शांति देखना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि हमारा देश खतरे में पड़े। इस लिये हमें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है।

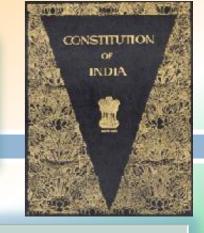
P. 03





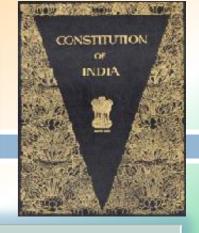
यह CAA + NPR (NRC) इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है, क्योंकि इस कानून को इस देश की आबादी की बड़ी संख्या को दो नंबर का नागरिक बनाने की तैयारी के रूप में लाया गया है, कुछ मनुवादियों ने तो खुले तौर पर कहा है कि ये कानून हिंदू राष्ट्र की ओर पहला कदम है। जाहिर है, आगे चल कर दूसरे नंबर के नागरिकों को मतदान के अधिकार, विचारों की अभिव्यक्ति के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है।





यह CAA + NPR (NRC) इस देश की गंगा-जमुनी सभ्यता के खिलाफ है; यह देश हमेशा अलग-अलग देशों और अलग-अलग धर्मों के लोगों के लिए एक आश्रय स्थल रहा है। प्राचीन काल से, दुनिया भर के लोगों ने इस देश में शरण ली है, जिस ने भी शरण माँगी भारत ने उसे शरण दी, इस पिवत्र भूमि ने कभी किसी शरण माँगने वाले से उसका धर्म नहीं पूछा, इस देश में हमेशा विभिन्न धर्मों और जातियों के लोग एक परिवार के सदस्य की तरह रहते आए हैं, यह कानून गंगा जमुनी सभ्यता के स्वच्छ जल को मैला करना, और लोगों को धर्म के आधार पर विभाजित करना चाहता है।

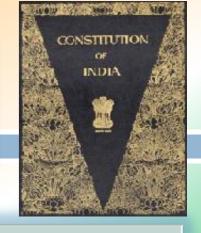




यह CAA + NPR (NRC) यह देश की आर्थिक स्थिरता के खिलाफ है, एक कारण यह है कि NRC (जिसके साथ यह कानून संबन्धित है), उस में सरकार को लाखों करोड़ों बल्कि अरबों-खरबों के बजट का खर्च आएगा, हमारे देश की अर्थव्यवस्था पहले ही काफी गिर चुकी है। एसी स्थित में अर्थव्यवस्था पर यदि लाखों करोड़ों बल्कि अरबों-खरबों का बोझ पड़ेगा तो आर्थिक स्थिति चुरमुरा के रह जाएगी। दूसरी बात, यह आर्थिक स्थिरता के खिलाफ इस लिये भी है कि देश में रहने वाले लोगों को सही से रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी दिन बदीन बढ़ती जा रही है। यदि सरकार देश की बेरोजगारी को खतम ना कर के बाहर से आने वालों को रोज़गार और अन्य सुविधाएं देगी तो इस का उदाहरण उस महिला की तरह होगा जो पड़ोस के किसी बच्चे को दूध पिलाए और अपने बच्चे को निर्दयता से रोता छोड़ दे। जाहिर है, अगर बाहर से आने वाले लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाता है, तो देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित होगी।

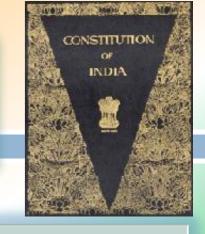
P. 06





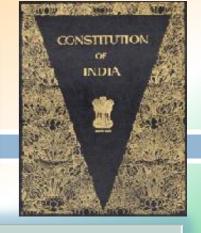
यह CAA + NPR (NRC) देश की पारदर्शिता के भी खिलाफ है। इस कानून के साथ, जब NRC या NPR की प्रक्रिया शुरू होगी, तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा, लोग अपने कागजात सही कराने, और नए कागजात बनवाने के लिए रिश्वत देंगे। मुंह माँगा पैसा देने पर मजबूर हुंगे। भ्रष्टाचार लकड़ी के घुन के समान है, जो स्पष्ट रूप से देश के लिये एक अच्छा संकेत नहीं है।





यह CAA + NPR (NRC) देश की गरिमा के खिलाफ है, यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की जगहसाई का कारण बनेगा, लोग कहेंगे क्या अजीब तर्क है कि एक बाहरी व्यक्ति के पास भारत का कुछ भी कागज ना होने के बावजूद उसे CAA द्वार भारत का नागरिक बनाया जा रहा है और भारती के पास कागज रहने के बावजूद कागज में कुछ गडबड़ी के कारण NRC से बाहर निकाला जा रहा है, अर्थात बाहरी कागज ना होने के बावजूद अंदर और अंदर वाला कागज रखने के बावजूद बाहर।

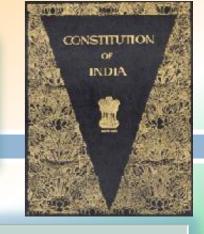




यह CAA + NPR (NRC) देश के सभी गरीबों के खिलाफ है, चाहे मुस्लिम हो या हिन्दू या कुछ और। इस के कारण सबसे ज्यादा नुकसान देश के गरीब लोगों का होगा, विशेषकर एससी, एसटी, आदिवासी और ओबीसी के लोगों का। कागज की ज्यादातर समस्याएं गरीब लोगों को होंगी, क्योंकि बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो भूमिहीन हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, यदि जमीन है तो कागजात नहीं हैं, यदि उनके पास कागजात हैं तो उतने पुराने नहीं हैं जितने पुराने मांगे जा रहे हैं, यदि उतने पुराने हैं भी तो उस में कुछ ना कुछ खराबी है। पैसे वाले लोग तो अपना उल्ल् सीधा कर लेंगे लेकिन ग़रीब धक्के खाते फिरेंगे।

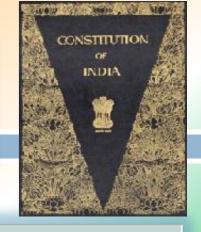
P. 09





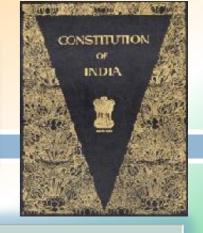
यह CAA + NPR (NRC) देश के सभी निवासियों के खिलाफ है, चाहे मुस्लिम हो या कोई और हो; क्योंकि कागजात बनाने या सही कराने या कोई और काम के लिए लाइनों में सभी को लगना होगा, नोटबनदी की लाइनों में खड़ा होना उतना मुश्किल नहीं था जितना NRC के लाइन में खढ़ा होना मुश्किल होगा। मुस्लिम हो या ना हो सब को इन कठिनाइयों से गुजरना होगा।





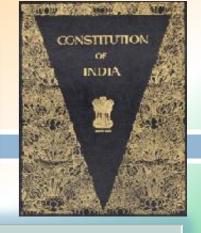
यह CAA + NPR (NRC) केवल मुसलमानों के खिलाफ इस लिये भी नहीं है कि मुसलमानों के अलावा अन्य समुदाय वालों की एक बड़ी संख्या को भी निरोध केंद्र (DETENTION CENTER) में डाला जाएगा। इसके पीछे सरकार के कई उद्देश्य होंगे। इस के लिये विशेष कर SC, ST और OBC का दुरुपयोग कया जा सकता है।





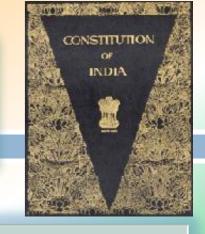
यह CAA + NPR (NRC) केवल मुसलमानों के खिलाफ इस लिये भी नहीं है कि बड़ी संख्या में अनय समुदाय के लोगों को सरकार द्वारा नागरिकता नहीं देने के लिए परेशान किया जा सकता है, जैसा कि असम में किया गया, सरकार उन्हें ना ही नागरिकता देगी और ना ही DETENTION भेजेगी। बल्कि एक लमबे समय तक बीच में लटका कर रखेगी, वे उन लोगों को फंसाने की कोशिश करेगी जो मनुवाद और संघवाद के खिलाफ हैं, चाहे वे उच्च जाति के धर्मनिरपेक्ष लोग हों या एससी, एसटी, आदिवासि और ओबीसी के लोग हों या वामपंथी हों।





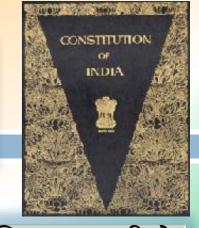
यह CAA + NPR (NRC) देश के सभी निवासियों के खिलाफ इस लिये है कि मुसलमानों के इलावा जो अन्य समुदाय के लोग NRC से बाहर होंगे उन में एक बहुत बड़ी संख्या एसी होगी जिनको सरकार ये जता कर नागरिकता देगी के हम तुम पर एहसान कर रहे हैं; ऐसा होने पर, उनकी गर्दन एहसान तले दब जाएगी और जबानों पर ताले लग जाएंगे। फिर ना कोई आरक्षण मांगेगा और ना ही कोई मनुवाद का विरोध करने का साहस रखेगा।





यह CAA + NPR (NRC) देश के सभी निवासियों के खिलाफ इस लिये है कि एनआरसी से बाहर आने वालों में मुस्लिमों के इलावा दूसरे लोगों के लिए सीएए के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने का दरवाजा खुला रहेगा, परन्तु यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जो भी एनआरसी से बाहर होगा उस को अवैध नागरिक घोषित किया जाएगा, जब वह अवैध निवासियों की सूची में आ जाएगा तो सरकार को उस की संपत्ति जब्त करने का अधिकार होगा। फीर जब उसे सीएए द्वारा लाया जाएगा तो उसे केवल नागरिकता दी जाएगी, संपत्ति नहीं। संपत्ति लौटाना सरकार के विवेक पर होगा। यहां चित भी संघी सरकार की और पट भी।

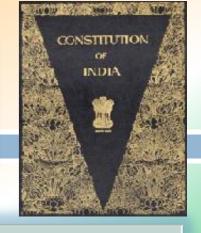




यह CAA + NPR (NRC) देश के सभी निवासियों के खिलाफ इस लिये है कि एनआरसी से बाहर आने वाले गैर-मुसलमानों के लिए, सीएए के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करना संभव है, लेकिन यह कानून तीन पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों के लिए है, अर्थात बाहरी लोगों के लिए है; इसलिए एनआरसी से बाहर होने वाला जब सीएए के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करेगा तो उसे सरकार ये नागरिकता एक विदेशी अप्रवासी मान कर देगी। जाहिर है, ये एक भारतीय के आत्म-सम्मान के खिलाफ है कि जिस देश में वह और उसके पूर्वजों ने अपना सारा जीवन गुजारा है उसी देश में उसे एक विदेशी अप्रवासी के रूप में नागरिकता स्वीकार करनी होगी। दूसरी बात यह कि जब सीएए के माध्यम से नागरिकता प्रदान की जाएगी तो चाहे एससी, एसटी और ओबीसी का क्यूँ ना हो उसे सामान्य वर्ग (GENERAL CATEGORY) की नागरिकता दी जाएगी।

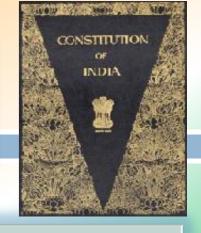
P. 15





यह CAA + NPR (NRC) देश के सभी निवासियों के खिलाफ इस लिये है कि यदि सीएए के माध्यम से कोई नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, तो उसे खुद को एक कागज पर विदेशी साबित करना होगा। अगर वे वास्तव में विदेशी होगा तो यह मुश्किल जरूर होगा परन्तु असंभव नहीं होगा। लेकिन यदि NRC से कोई भारतीय बाहर हो जाए तो वह अपने आप को विदेशी कहां से साबित कर पाएगा, वह सरकार की दया पर होगा, मनुवादी सरकार की दया पर होने का क्या मतलब हो सकता है हर कोई समझ सकता है।

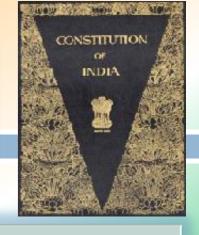




यह CAA + NPR (NRC) देश के सभी निवासियों के खिलाफ इस लिये है कि NRC और CAA की गोटी सेट करके, मनुवाद का विरोध करने वालों के खिलाफ एक बड़ा खेल खेला जाएगा। अर्थात् SC, ST और OBC का आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। जब उन्हें नागरिकता दी जाएगी तो सामान्य वर्ग की नागरिकता दी जाएगी, और ये लोग यह सोचेंगे कि नागरिकता नहीं होने से लाख गुना बेहतर है कि सामान्य वर्ग की नागरिकता प्राप्त कर ली जाए। इस तरह, संघवाद के तीर अपने निशाने पर जा लगेंगे।

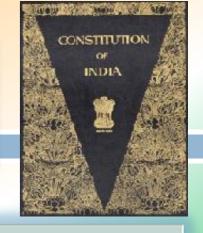
P. 17 NO NPR - NO NRC - NO CAA





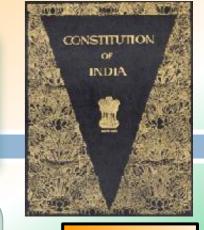
यह CAA + NPR (NRC) देश के सभी निवासियों के खिलाफ इस लिये है कि सीएए और एनआरसी या एनपीआर का पूरा खेल मनूवाद और ब्राहमणवाद लाने के लिए खेला जा रहा है, एनआरसी से मुसलमानों को बाहर किया जाएगा, तो उनके पास डिटेंशन और मौत के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। जबिक सीएए का चारा फेंक कर SC, ST और OBC के लोगों को विभिन्न रूप से ब्राहमणवाद के जाल में फंसाया जाएगा। ये बात भी स्पश्ट होनी चाहिये कि संघ के एजेंडे में, मुसलमानों के अतिरिक्त दो वर्ग या समुदाय और हैं, जिन्हें भविष्य में निशाना बनाया जाएगा, और वे कम्युनिस्ट (वामपंथी) और ईसाई (क्रिसचन) हैं, शायद कम्युनिस्टों की बड़ी संख्याभी से ये लोग इसी एनआरसी ही में निपट लें।





अंत में, यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि सरकार ने NRC पर होरहे बवाल को देखते हुए NPR को लाने की बात शुरू कर दी है। NPR अपने वर्तमान रूप में या तो एनआरसी का ही काम करेगा या कम से कम एनआरसी का रास्ता आसान करेगा। एनपीआर वास्तव में एनआरसी का पहला चरण है। यह बात ग्रह मंत्रालय द्वारा प्रकाशित २०१८-२०१९ की वार्षिक रिपोर्ट के पेज २६२ पर स्पष्ठ रूप से लिखा हुवा है। इसलिए एनआरसी के संबंध सभी बातें एनपीआर पर भी लागू होती हैं। इसलिए कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए।





S S

इस पूरे लेख का सार यह है कि अगर हम देश को, देश की अखण्डता को और धर्मनिरपेक्षता को बचाना चाहते हैं, तो मनुवादियों की चालों को समझें और एनअरसी और एनपीआर का संपूर्ण बहिष्कार करें। इस के सिवा कोई रास्ता नहीं है।

आर एस एन

P. 20